have been obtained. That is about Rs. 44 lakhs and the balance foreign exchange required is a very little amount and it will also be released.

Shri J. P. Jyotishi: May I know whether there is any disagreement between the Government of Madhya Pradesh and the Government of Uttar Pradesh regarding the distribution of electricity?

Mr. Speaker: That has also been answered.

Shri Sheo Narain: May I know what was the estimate in 1958 and what is the estimate now?

Mr. Speaker: That has also been answered.

Shri Bade: Sir, there is my request. In the first place, he said that Madhya Pradesh is not considered at all. In another place, he said that Madhya Pradesh is entitled to have some quota of the power. I want to ask whether the Madhya Pradesh has got more power according to his statement?

Mr. Speaker: He has said that Madhya Pradesh was not a participant in that. Now a representation has been made and it would be considered if something can be given to Mr. Bade.

Coal Transport

\+

*665. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri B. K. Das:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Daji:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 376 on the 29th August, 1963 and state:

(a) whether the team of foreign consultants has submitted its report about the coal transport problem in India;

(b) if so, the main suggestions made in the report; and

(c) if not, the reasons for delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): (a) The team has submitted an interim report.

(b) The main suggestions made in the report are laid on the Table. [*Placed in Library. See* No. LT-2189/63].

(c) Does not arise.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं इस का हिन्दी में भी उत्तर बतला दूं क्योंकि प्रश्न केवल अंग्रेजी में था ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (क) टीम ने एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है ।

(ख) जो उस के सुझाव हैं वे सभा के पटल पर रक्खे गये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि टीम ने जो सुझाव दिये हैं उन का परिपालन सरकार कब तक कर देगी और कितनी हद तक ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो मौजूदा सुझाव दिये गये हैं वे यह मद्दे नजर रख कर दिये गये हैं कि उन का प्रतिपालन तुरन्त हो जाय और जिन मंत्रालयों को उन का प्रतिपालन करना है वे इस पर गौर कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसे पूरा करेंगे । रेलवे मंत्रालय है और जिस मंत्रालय का कोयले से ताल्लुक है वे सब विभाग इस के बारे में तुरन्त कार्रवाई कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रश्न का जवाब सिर्फ इतना हो कि "Statement is laid on the Table of the House" या यह कि "the question does not arise" और हिन्दी में हो कि "विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है या यह कि "प्रश्न नहीं उठता" तो उस का दूसरी भाषा में तर्जमा करने की

जरूरत नहीं है । अब माननीय सदस्यों को कोशिश करनी चाहिये कि एक दूसरे की जबान को ज्यादा समझें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि स्टेटमेंट सदन पटल पर रख दिया गया है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो कागजात सदन पटल पर रक्खे गये हैं उन में यह रिपोर्ट नहीं है । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट का मुख्य सारांश क्या है और उस के परिणाम-स्वरूप क्या फायदा हुआ ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो स्टेटमेंट मैं ने रखा है उस में जो मुख्य सुझाव हैं वे दिये हुए हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : उन में नहीं है । जो कागजात बांटे गये हैं उन में मुझे नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : था या नहीं इस का फैसला हो जायेगा बाद में ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दिया जाय ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उसे सभा पटल पर रख दिया गया है लेकिन अगर माननीय सदस्य को नहीं मिले हैं और वह कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं दे देती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर जो विवरण रक्खा गया है उस में क्या यह रिपोर्ट है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय सभा पटल पर जो कागजात रखे जाते हैं वे हमको आधे घंटे पहले मिल जाते हैं । लेकिन इस सवाल के मुताल्लिक कागजात हमको नहीं मिले हैं इसलिए हम कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते । इसलिए मैं चाहता हूं कि वह स्टेटमेंट हमको बता दिया जाए । उसको केवल सभा पटल पर रखने से हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि वह हमको नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर जो कागजात रखे जाते हैं उनकी नक्लें नोटिस आफिस में मिलती हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : नहीं मिलीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी तहकीकात कर लूंगा कि क्यों नहीं मिलीं । लेकिन जो ब्यान दे दिया जा चुका है उस पर बार बार कितने सवाल दुहराता चला जाऊं ।

Shri Daji: What steps have been taken to ensure that the default of the railways, which has been pointed out as one of the major factors contributing to the bottle-necks in coal transport, is remedied in a very short time and the bottle-neck is removed?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I am afraid that the question has an implication that there is default on the part of the railways. It is not conceded.

Mr. Speaker: Shri Bhagwat Jha Azad.

Shri Daji: I seek your protection, Sir.....

Mr. Speaker: Order, order. I have called Shri Bhagwat Jha Azad now.

श्री भगवत झा आजाद : क्या इस अन्तरिम रिपोर्ट के अलावा ऐसा भी कोई संकेत उन्होंने किया है कि वे कब तक अन्तिम रिपोर्ट देने में समर्थ हो सकेंगे ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अनुमान है कि मार्च/अप्रैल सन् १९६४ तक यह रिपोर्ट पेश हो जाएगी ।

Shri Daji: My submission is that the hon. Minister has taken shelter behind the use of the term 'default'. But, as far as we learn, one of the causes pointed out by the team is—we may not use the word 'default', but we may use the word 'shortage'

—shortage of railway wagons and rolling-stock; that has been said to be one of the premier reasons for bottle-neck in coal transport. Could the hon. Minister enlighten us as to the immediate steps that are being taken to ensure that this bottle-neck is removed? The hon. Minister has taken exception to the use of the word 'default' and he says that there is no default. Let him answer at least this question.

Mr. Speaker: The hon. Member had used the word 'default'. The answer is that there is no default and the presumption of the hon. Member is wrong. Now, he has modified the question and says that if there is no default then there may be shortage. That would be a fresh question altogether.

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कंसलटेटिव कमे कौन से मेम्बर हैं और उन के मुख्य सुझाव क्या हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो मुख्य मुख्य सुझाव थे वे स्टेटमेंट में दे दिए गए हैं । जिस स्टीयरिंग कमेटी ने इसके बारे में कुछ कार्रवाई की है उसके दो मेम्बर हैं । उस कार्रवाई के बाद रिपोर्ट लिखने के लिए कंसलटेटिव कमेटी को दे दी गयी जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं । स्टीयरिंग कमेटी के एक मेम्बर हैं श्री जी० एल० बंसल, सेक्रेटरी जनरल इंडियन चेम्बर आफ कमर्स, और दूसरे हैं श्री एडवर्ड मैसन, हारवर्ड यूनीवरसिटी के ।

Anti-Fraud Squad

\+

*6. **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri Maheswar Naik:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are contemplating the setting up of a high-power anti-fraud squad to check and penalise economic offences in the Corporate Sector; and

(b) if so, when the proposal is likely to be put into effect?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b) The question of widening the scope of work of the enforcement staff under the Ministry of Finance and of strengthening that staff to cope with the increased work is under consideration. It is however not possible to state precisely when the reorganised arrangement will be given effect to.

Shrimati Savitri Nigam: May I know the names of the members of this committee which is going to give its final decisions?

Shri B. R. Bhagat: It is done by the Department, by the officers concerned, and finally, the Finance Minister will take a decision on this.

Shrimati Savitri Nigam: May I know in what way this committee is intended to strengthen this whole unit, and in what way it is going to make it more and more effective?

Shri B. R. Bhagat: This is being done by the Ministry. There is no committee.

Shri Kapur Singh: May I know whether Government have made a proper examination of the merits and demerits of the question of in-built checks versus exterior controls, and if so, whether they will give a second look to this innovation of squad inspections of Government offices?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I could not catch the question.

Mr. Speaker: I could not understand it. I must confess that.

Shri Kapur Singh: I am very sorry. I shall try to make myself clearer. Have Government examined whether in administration in-built checks are more effective or sporadic exterior controls are more effective, and if they have, will they give a second look to this innovation of outsider squads swooping on offices? Is the question clear now?